अनुलग्नक

जून, 2023 माह के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों का मासिक सार

I. स्वच्छ भारत मिशन

i. सभी 4,715 शहरों/कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तृतीय पक्ष सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ+, 1191 शहरों को ओडीएफ++ और 14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरूपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापत्तनम, कराड, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को वॉटर+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालय "एसबीएम शौचालय" के नाम से गूगल मानचित्र पर लाइव हैं।

iii. स्वच्छता ऐप एक ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है जो नागरिकों को सक्षम बनाने की दिशा में कार्यरत है ताकि उनकी शिकायतों का संबंधित नगर निगम द्वारा समाधान किया जा सके। स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें पोस्ट की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया गया है, जिनमें से 94% से अधिक का समाधान किया जा चुका है।

iv. जीएफसी 2022 का परिणाम 01 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2022 के भाग के रूप में घोषित किया गया था। कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 7-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 1 है, 5-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 11 है, 3-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 199 है और 1-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 234 है।

v. दिनांक 09.06.2023 को सचिव, आवासन और शहरी कार्य की अध्यक्षता में बायो-सीएनजी संबंधी एक समीक्षा बैठक की गई।

vi. राष्ट्रीय सलाहकार और समीक्षा समिति (एनएआरसी) की बैठक 8 जून, 2023 को सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 9 राज्यों के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, प्रयुक्त जल प्रबंधन, क्षमता निर्माण और आईईसी की स्थापना के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए हुई, जिसमें 2,450 करोड़ रु. की कार्य योजनाएँ स्वीकृत की गई थीं।

vii. 15 और 16 जून, 2023 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के सहयोग से प्रयुक्त जल फीकल स्लज प्रबंधन प्रणालियों पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई थी।

viii. सचिव, आवासन और शहरी कार्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का क्षेत्र मूल्यांकन किया।

ix. सीबीजी संयंत्रों पर अनुभव साझा करने और सीखने के लिए जीआईजेड के सहयोग से इंदौर में सीबीजी संयंत्रों के कार्यान्वयन पर 27.06.2023 - 28.06.2023 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

II. स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)

i. 1,79,165 करोड़ रू. की 7,973 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 1,07,683 करोड़ रू. की 5,858 परियोजनाएं पहले ही पूर्ण की जा चुकी हैं।

ii. इस माह 766 करोड़ रुपये की 85 अतिरिक्त परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं।

iii. अभियान आईटीडीपी इंडिया के सहयोग से स्मार्ट सिटीज मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 'फ्रीडम2वॉकसाइकिलरन' का शुभारंभ किया गया था। एफ2डब्ल्यूसीआर अभियान 100 स्मार्ट शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सिटी मार्गदर्शकों में पैदल चलने, साइकिल चलाने और दौड़ने को बढ़ावा देने के लिए हर तिमाही में 45 दिनों के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

iv. 25 जून 2023 को, स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने मिशन की 8वीं वर्षगांठ का जोशपूर्ण जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में सभी 100 शहरों से सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता भी देखी गई। स्मार्ट सिटीज मिशन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल www.youtube.com/@SmartCitiesMission पर दस विषयगत वीडियो जारी किए गए, जो स्मार्ट सिटीज मिशन की प्रभावशाली जन-केंद्रित कहानियों को बयान करते हैं।

v. अब तक, 100 स्मार्ट शहरों ने आठ विषयों में से एक या अधिक (अर्थात् वोकल फॉर लोकल, देश की एकता (युनिटी बाय टेक), स्थायी विकास, आत्मनिर्भर भारत, समावेशी विकास, स्वास्थ्य और कल्याण, महिला और बाल सशक्तिकरण, स्वतंत्रता संग्राम) पर 150+ ऑनलाइन/ऑफ़लाइन कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 5,00,000 से अधिक नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

vi. **04 जून 2023** को, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम (ट्यूलिप) ने तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस कार्यक्रम के तहत, कई यूएलबी में 8,500 से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए हैं।

vii. **मिशन में उल्लेखनीय प्रगति**

- **<u>जीवंत सार्वजनिक स्थान:</u>** 1,027 से अधिक पार्क, हरे-भरे स्थान और झील के किनारे/नदी के किनारे सैरगाह विकसित किए गए, 47 शहरों में 180 तटवर्ती परियोजनाएं।

- **<u>आर्थिक केंद्र</u>** : 15 इनक्यूबेशन सेंटर/कौशल विकास केंद्र विकसित हुए और 200 से अधिक बाजार पुनर्विकास परियोजनाएं पूरी हुईं।

- **<u>गतिशीलता:</u>** 2,500+ किलोमीटर से अधिक स्मार्ट सड़कों का निर्माण/सुधार किया गया है और 573 किलोमीटर साइकिल ट्रैक विकसित किए गए हैं।

- **<u>स्ट्रीटलाइट्स</u>**: 17.36 लाख से अधिक एलईडी/सोलर स्ट्रीटलाइट्स स्थापित की गईं और 8,175 किलोमीटर से अधिक भूमिगत बिजली केबल का निर्माण किया गया।

- **<u>शहरों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी</u>**

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** : आईसीसीसी के माध्यम से 80 से अधिक शहर एसडब्ल्यूएम की निगरानी कर रहे हैं। 2 लाख से अधिक आरएफआईडी सक्षम **ई-वेस्ट डस्टबिन** स्थापित किए गए।

- **जल आपूर्ति** : 93 शहरों में 347 परियोजनाएं, 25+ शहर स्काडा प्रणाली के माध्यम से जल आपूर्ति पाइपलाइनों की निगरानी कर रहे हैं।

- **शिक्षा** : 6,800 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए गए हैं, 1600 आंगनवाड़ियों और 40 शहरों में डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की गई हैं।

- **स्वास्थ्य** : 308 ई-स्वास्थ्य केंद्र और क्लीनिक विकसित किए गए हैं (बिना विशिष्ट बिस्तरों के), 480 स्मार्ट एम्बुलेंस बढ़ाई गई हैं और 255 स्वास्थ्य एटीएम स्थापित किए गए हैं।

- **वाईफाई और सर्विलेंस** : 9,732 वाईफाई हॉटस्पॉट स्थान बनाए गए और 76,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. आज की स्थिति के अनुसार, 77,640 करोड़ रू. की अनुमोदित कार्य योजना से अधिक 83,137 करोड़ रू. की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी गई है। कुछ राज्यों ने अपने अनुमोदित एसएएपी से

अधिक परियोजनाएं आरंभ की हैं, जिसमें अतिरिक्त राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी। 38,645 करोड़ रुपये की 4,967 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया चुका है और 43,992 करोड़ रुपये की 921 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, पूर्ण/चालू अमृत परियोजनाओं में लगभग 72,304 करोड़ रू. का वास्तविक कार्य किया गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 93% वास्तविक कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई), सुधार प्रोत्साहन के लिए और 'अमृत शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने और 25 चयनित शहरों में स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और कस्बा नियोजन योजनाएं (टीपीएस)' पर उप-योजनाओं के तहत 38,469 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

IV. दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)

i. चालू वित्तीय वर्ष के जून माह के दौरान 8,544 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है; 3,234 एसएचजी को परिक्रामी निधि दी गई है; व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए लाभार्थियों को ऋण की सहायता प्रदान की गई और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 10,654 ऋण दिए गए।

V. पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि)

i. पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) के तहत 66,80,171 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए 50,99,773 स्वीकृतियां दी गई हैं और 48,55,998 संवितरण किए गए हैं।

ii. जून, 2023 के दौरान मिशन के तहत कुल 3.609 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

VI. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सबके लिए आवास (एचएफए)

i. स्थापना के बाद से, मिशन में 1.19 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 112.12 लाख आवासों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है, जिनमें से 75.22 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/सुपुर्द किए जा चुके हैं।

ii. जून, 2023 माह के दौरान पीएमएवाई(यू) के तहत 948.84 करोड़ रू. जारी किए गए हैं ।

VII. आवास

i. नागालैंड, जो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

ii. *32* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा नियामक प्राधिकरण की स्थापना की है। *लद्दाख, मेघालय और सिक्किम ने प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अभी तक नियमों को अधिसूचित नहीं किया है।*

iii. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित-24, अंतरिम-04) की स्थापना की है *(अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं)।*

iv. 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटें चालू कर दी हैं। *(अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर अपनी वेबसाइटों को चालू करने की प्रक्रिया में हैं)।*

v. देशभर में 1,08,856 भू-संपदा परियोजनाओं और 77,864 भू-संपदा एजेंटों का रेरा के तहत पंजीकरण किया गया है।

vi. देश में भू-संपदा नियामक प्राधिकरणों द्वारा 1,11,302 शिकायतों का निपटान किया गया है। इस माह के दौरान 1,545 परियोजनाएं और 879 एजेंट पंजीकृत किए गए हैं।